

अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 51 | आगरा, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

देशभर में बारिश का कहरः उत्तराखंड-जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड, श्रद्धालुओं की यात्रा रुकी

केदारनाथ मार्ग बंद, 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव से जनजीवन प्रभावित

नई दिल्ली,(ए)। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान सहित 16 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं के कारण सड़क संपर्क बाधित हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अलर्ट हैं।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में गुरुवार सुबह कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण केदारनाथ ट्रैकिंग मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग के सिल्ली क्षेत्र में मलबा



आने से राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए बाधित रहा, जबकि पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव के बीच गंगाजल भरने उतरा एक युवक नदी में बहने लगा। मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी क्षेत्र और कुपड़ा गांव के पास भी भारी बोल्डर और मलबा सड़क तक आ गया, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।

स्कूल की दीवार ढही

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के चलते एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की दीवार ढह गई। वहीं अक्चमल क्षेत्र में भूस्खलन के बाद कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी।

कई गांव नदी के कटाव की चपेट में

उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी के कटाव ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सौ से अधिक परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और दो मकान नदी में समा चुके हैं। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर घटने के बावजूद कटान तेज हो गया है, जिससे कृषि भूमि और पेड़ नदी में बह रहे हैं।

भारी बारिश का अलर्ट जारी

इधर, मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शियर जोन जैसे तीन मजबूत मौसम तंत्र प्रभावी होने से उज्जैन, सागर सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

दीपके ने कहा- जरुरत पड़ी तो कल ही बदल देंगे सरकार

छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं होने भड़की सीजेपी



नई दिल्ली(ए)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो उनका संगठन नए सिरे से बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को परेशान करना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। दीपके ने यह भी कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं, उन्हें अपराधियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग अपनी पर आ गए तो कल ही सरकार बदल देंगे।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लोगों का आक्रोश खत्म हो गया है, तो यह उसकी गलतफहमी है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों और युवाओं में अब भी व्यापक नाराजगी है और यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो अगला आंदोलन पहले से कहीं बड़ा होगा। एक सवाल के जवाब में दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने की बात भी कही। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक जीवन में दूसरी भूमिका अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करेगी तो युवा लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे।

दीपके ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली में लगभग एक महीने तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि करीब 40 दिन बाद अपने घर लौटने पर उन्हें सबसे अधिक खुशी अपने माता-पिता से मिलने की है। उनके अनुसार, भारत आने के बाद से वह लगातार आंदोलन में व्यस्त रहे और लगभग 36 दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिताए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कई राज्यों में छात्रों को परेशान किया जा रहा है।

सख्त सजा से ज्यादा जरुरी है पेपर लीक होने की संभावना को खत्म करना



नई दिल्ली(ए)। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार को लोकसभा से ध्वनिमत से पारित करा लिया। विधेयक में पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों के लिए कड़ी सजा, भारी जुर्माने, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इस कानून को अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के मूल उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार का ध्यान मुख्य रूप से पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई पर है, जबकि सबसे जरूरी सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को होने से पहले कैसे रोका जाए। उनके अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त सजा और भारी जुर्माना आवश्यक हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को दूर किए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। रांका ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में व्यापक सुधार किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को वैधानिक निकाय का दर्जा मिले, परीक्षा कैलेंडर और पाठ्यक्रम में पारदर्शिता लाई जाए तथा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े वेंडरों और कोचिंग संस्थानों की सख्त निगरानी हो। उन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्ट किए गए वेंडरों को दोबारा काम करने से रोकना, डिजिटल और भौतिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना तथा पूरी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। उनका कहना है कि यह केवल कानून का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा भी हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करने या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने पर न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की सजा तथा 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सात वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के अंदर मुकदमे का निपटारा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस बीच केंद्र सरकार पहले ही परीक्षा सुधारों के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है। यह समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक सुझाव तैयार करेगी।

मोहम्मद इरफानः एक वायरल आवाज, त्याग और संघर्ष की कहानी

नई दिल्ली (ए)। दिल्ली की जेजे पुनर्वास कॉलोनी के मोहम्मद इरफान का वीडियो आज पूरे देश में देखा जा रहा है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कैमरे के सामने कुछ मिनट की उनकी बातचीत ने उन्हें चर्चित चेहरा बना दिया। उनके परिवार के अनुसार, इरफान आज देश की आवाज बने हैं। उनकी मां नम आंखों से कहती हैं, हम लोगों ने अपने बेटे को देश को दे दिया है। पहले उसके बाहर जाने पर डर लगता था, अब लगता है कि वह लोगों की आवाज बन गया है। वहीं, उनके 77 वर्षीय पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे का नाम हो रहा है।

लेकिन वायरल चेहरे के पीछे संघर्ष, त्याग और परिवार की ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिस युवक को आज संविधान, लोकतंत्र और मजदूरों के अधिकारों पर चर्चा करते सुना जा रहा है, उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में भी परिवार को खुद से आगे रखा। इरफान ने अपनी तय हो चुकी सगाई इसलिए तोड़ दी ताकि पहले छोटे भाई की शादी और बहनों की जिम्मेदारियां पूरी की जा सकें। उनकी मां कहती हैं कि उन्होंने परिवार को साफ कह दिया था कि वह अभी शादी नहीं करने वाले है। परिवार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और सगाई टूट गई। इसके बाद परिवार ने छोटे बेटे की शादी की और अब बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करने की तैयारी कर रहा है।

इरफान का परिवार आज भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। उनके माता-पिता बताते हैं कि परिवार चलाने के लिए इरफान ने हर तरह का काम किया। कभी फल बेचे, कभी माली का काम किया, कभी झुग्गियां बनाई और जब झुग्गियां टूट गई, तब गहने तक बेचने पड़े। आज भी परिवार बर्फ बेचकर अपनी रोजी-रोटी चला रहा है। मां कहती हैं कि मुश्किलें बहुत आई, लेकिन बच्चों को कभी गलत रास्ता नहीं अपनाने दिया, हमेशा ईमानदारी और मेहनत करना सिखाया।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ही जब नीली टी-शर्ट पहने इरफान कैमरे के सामने आए। कुछ मिनटों में ही उन्होंने लोकतंत्र, संविधान, मजदूरों के अधिकार और मानवीय गरिमा जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उनकी सरल भाषा सीधे लोगों तक पहुंची और वीडियो वायरल होने के बाद लाखों लोग जानना चाहते थे कि आखिर यह मोहम्मद इरफान कौन हैं। वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद इरफान के घर पहुंचे। मुलाकात के दौरान सुरक्षा कारणों से जब पत्रकार को बाहर रोका गया, तब इरफान ने सुरक्षाकर्मियों से कहा, पत्रकार को अंदर आने दीजिए... मैं पत्रकार के बिना अधूरा हूं। राहुल गांधी से मुलाकात में इरफान ने अपने लिए कोई व्यक्तिगत मदद नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अगर कुछ करना है, तब गरीबों और मजदूरों के लिए किया जाए।

हालात बिगड़ रहेः यूक्रेन ने कहा- भारत बात नहीं कर रहा, 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

नई दिल्ली,(ए)। यूक्रेन ने ब्लैक सी (काला सागर) में सुरक्षा हालात को लेकर भारत की हालिया समुद्री एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन का कहना है कि क्षेत्र में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के बावजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एमवी एएमआईआर1 जहाज में 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं।



नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने नौवहन महानिदेशालय की ओर से जारी दो अलग-अलग सुरक्षा एडवाइजरी की तुलना करते हुए सवाल उठाए हैं। यूक्रेन के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए जारी एडवाइजरी में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और शिपिंग कंपनियों को अगले आदेश तक उस क्षेत्र में भारतीय चालक दल भेजने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं, ब्लैक सी के लिए जारी एडवाइजरी में ऐसी सख्ती नहीं दिखाई गई। यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि ब्लैक सी में लगातार हमलों के बावजूद सुरक्षा उपायों का स्तर वहां मौजूद खतरे के अनुरूप होना चाहिए। यूक्रेन का दावा है कि नागरिक जहाजों पर हो रहे हमलों में भारतीय नाविक भी प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। यूक्रेन के अनुसार, विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यूक्रेन का कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बढ़ाना चाहता है।

एमवी एएमआईआर1 जहाज पर फंसे 13 भारतीय नाविकों को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास भी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय दूतावास ने पहले ही कहा था कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास कर रहा है। यूक्रेन ने भारतीय नाविक संघ की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। यूक्रेनी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि भारत का विदेश मंत्रालय और नौवहन महानिदेशालय ब्लैक सी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यह मामला समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रहा है।

अब ब्रिटेन तक अडानी का साम्राज्य? 21 पोर्ट खरीदने की तैयारी!

नई दिल्ली(ए)। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ब्रिटेन के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स (एबीपी) में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। यदि यह रणनीतिक सौदा सफल होता है, तो अडानी समूह का साम्राज्य भारत से लेकर ब्रिटेन तक फैल जाएगा। यह कदम अडानी ग्रुप की वैश्विक बंदरगाहों में उपस्थिति को और अधिक मजबूत करेगा और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने के उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को एक बड़ी गति प्रदान करेगा।



जानकारी के अनुसार, एबीपी की लगभग 63.9 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में यह हिस्सेदारी कनाडा के दो प्रमुख पेंशन फंड- कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) और आंटारियो म्युनिसिपल इम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम के पास है। दोनों निवेशकों ने अपनी-अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंकरों की नियुक्ति कर दी है। एबीपी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में कुल 21 बंदरगाहों का संचालन करता है। इनमें ब्रिटेन का सबसे बड़ा बंदरगाह इमिंघम और प्रमुख आयात बंदरगाह साउथेम्प्टन शामिल हैं। यह कंपनी ब्रिटेन के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा संभालती है। वर्ष 2025 में एबीपी ने 42.5 मिलियन टन बल्क कार्गो तथा 3.1 मिलियन कंटेनर और रोल-ऑन/रोल-ऑफ यूनिट्स का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इस दौरान कंपनी का राजस्व 819.8 मिलियन पाउंड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 586.5 मिलियन पाउंड दर्ज किया गया था। लोंगटर्म अनुबंधों से मिलने वाली स्थिर आय के कारण यह संपत्ति अडानी पोर्ट्स के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नड्डा संग टीएमसी नेताओं ने किया भोजन शत्रुघ्न सिन्हा पर टिकी नजर

कोलकाता(ए)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तस्वीर ने इन दिनों नई बहस छेड़ दी है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत रॉय की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोनों वरिष्ठ टीएमसी नेताओं का नड्डा के साथ बातचीत करना और भोजन करते हुए तस्वीर सामने आना, राजनीतिक अटकलों को तेज़ कर गया है, हालांकि इस मुलाकात के पीछे के वास्तविक कारणों पर अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।दरअसल, संसद के एनेक्सी भवन में बुधवार को क्षय रोग (टीबी) से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के कई सांसद शामिल हुए। इसी दौरान एक ऐसा क्षण कैमरे में कैद हो गया, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और अनुभवी सांसद सौगत रॉय एक ही जगह पर, एक ही मेज पर बैठे नजर आए। यह तस्वीर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने जेपी नड्डा से काफी देर तक बातचीत की। उसी मेज पर सौगत रॉय भी बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे। हालांकि, इन तीनों नेताओं के बीच आखिर क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भी आधिकारिक या अनौपचारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, और यही चुप्पी राजनीतिक अटकलों को और भी ज़्यादा गहरा कर रही है। बाद में एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें जेपी नड्डा भोजन करते दिख रहे थे जबकि सौगत रॉय उनके सामने खड़े दिखाई दिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे किए जाने लगे।

प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई में एक छात्र ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, अब जवाब दें

सीजेपी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी के गृहमंत्री पर लगाए आरोपों को रिशेयर किया

नई दिल्ली,(ए)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पोस्ट को रिशेयर किया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेग गन चलाए गए, जिसकी जिम्मेदारी गृह अमित शाह की है। हालांकि अमित शाह पर लगाए आरोप को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। इस पर सौरव दास ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की उससे गृह मंत्री पर सवाल उठते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सौरव दास ने लिखा कि 20 जुलाई को हुई पुलिस की बर्बरता के मामले में गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हर जिंदगी कीमती है। गृह मंत्री के आदेश पर एक छात्र ने हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब जवाब दें। संसद के मानसून सत्र में 29 जुलाई को राहुल गांधी ने छात्रों के चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोरदार विरोध शुरू हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने सीधे गृह मंत्री का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर आरोप है। आपको या तो माफी मांगनी होगी या फिर यह बताना होगा कि आपने किस आधार पर यह आरोप लगाया है।

इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सदन में बिना पूर्व सूचना और तथ्यों के आधार पर किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वे विधेयक पर चर्चा करें और केवल तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश पर ही होता है, किसी और के आदेश पर नहीं। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री जवाब दो और जवाब दो के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे सदन में शोर-शराबा हुआ।